

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली । शनिवार, 4 जून 2022

लोगों ने दिए सुझाव, अंडरपास और फ्लाईओवर से घटेगा जाम

■ विशेष संवाददाता, द्वारका

द्वारका की सड़कों पर बढ़ रहे जाम को लेकर अब द्वारका फोरम की तरफ से डीडीए के चीफ इंजीनियर को कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें एक तरफ पालम और शाहबाद मोहम्मदपुर रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग शामिल है, वहीं दूसरी तरफ पालम-द्वारका फ्लाईओवर को चौड़ा किए जाने की बात कही गई है। द्वारका फोरम की तरफ से प्रेजिडेंट सुशील कुमार, जनरल सेक्रेटरी एस छटवाल आदि इस मीटिंग में शामिल हुए।

फोरम की ओर से बताया गया कि मीटिंग में डीडीए अधिकारियों से सवाल भी किए कि इससे पूर्व में किए गए जॉइंट सर्वे के काम कब तक हकीकत में बदल जाएंगे। इन कामों में द्वारका की इंटरनल सड़कों का निर्माण, मास्टर प्लान सड़कों की कारपेटिंग, डीडीए के खाली प्लॉट की टूटी चारदिवारी को बनाना, नालों की सफाई, खुले नालों को कवर करना और राउंडअबाउट को खूबसूरत करना शामिल हैं।

इसके अलावा द्वारका फोरम की तरफ से द्वारका मोड़ के टी पॉइंट पर फ्लाईओवर, सेक्टर 1, 2, 6 व 6 के इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर, विभिन्न क्रॉसिंग पर स्लिप रोड आदि बनाने की मांग भी की गई है। साथ ही सेक्टर-4, 5, 11 और 12 की मार्केट, रामफल



द्वारका फोरम से जुड़े लोगों ने डीडीए के चीफ इंजीनियर को दिए सुझाव

ये हैं मांगें और सुझाव

- पालम और शाहबाद मोहम्मदपुर रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग
- पालम-द्वारका फ्लाईओवर को चौड़ा करने से लोगों को जाम से मिलेगी बड़ी राहत

चौक, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्टर-8 के पास मल्टीलेवल कार पार्किंग की मांग भी की गई है। फोरम की ओर से बताया गया कि इसके साथ ही द्वारका के फुटपाथ और सर्विस लेन को दुरुस्त करना, जेब्रा क्रॉसिंग को पेंट करना और डिवाइडर पर गायब हो चुकी ग्रिल को दोबारा लगाने की मांग भी की गई है।

यमुना खादर से हटाए गए 20 धोबी घाट

■ एनबीटी न्यूज, मयूर विहार : डीडीए ने यमुना खादर में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। गुरुवार को मयूर विहार फेज-1 और अक्षरधाम मंदिर के पास यमुना खादर में 20 धोबी घाट पर कार्रवाई पर अतिक्रमण मुक्त कराया है। डीडीए के अधिकारियों के कहना है कि यमुना

खादर में अवैध रूप से चल रहे सभी धोबी घाट पर डीडीए की कार्रवाई जारी रहेगी। मयूर विहार फेज-1 और अक्षरधाम मंदिर के पास यमुना में कई जगह पर अवैध रूप से धोबी घाट चल रहे थे। यहां अवैध रूप से द्यूबवेल लगाकर कुंड भी बनाए गए थे। जहां कपड़ों की धुलाई हो रही थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS:

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली
रविवार
5 जून 2022

DATED

पहली बार छह से ज्यादा स्थानों पर पानी रोकने की व्यवस्था की गई है, आसपास के क्षेत्र में भूमिगत जल के स्तर में बढ़ोतरी होगी तिलपथ घाटी में बारिश का पानी सहेजा जाएगा



विश्व
पर्यावरण
दिवस

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अरावली की तिलपथ घाटी में बारिश का पानी सहेजा जाएगा। इससे जहां जंगल की हरियाली बढ़ेगी वहीं भूमिगत जल संभरण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिए घाटी में छह से ज्यादा स्थानों पर चेक डैम बनाए गए हैं।

राजधानी दिल्ली के पर्यावरण में सुधार और वनों के संरक्षण के लिए डीडीए की ओर से वर्ष 2015 में लगभग 175 जमीन पर तिलपथ घाटी जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है। तब से ही यहां पर वनों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहां पर 484 प्रजाति के पेड़-पौधे, झाड़ियां व घास मौजूद हैं। यहां पक्षियों की 125 और तितलियों की 55 प्रजातियां वास करती हैं। हाल के दिनों



2015

अरावली की तिलपथ घाटी में पहले हरियाली की जगह जमीन नजर आती थी। हरियाली न होने से जीव-जंतुओं की आवाजाही कम थी।

में यहां पर सिक्का हिरन, सांभर और नीलगाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। दुर्लभ माना जाने वाला कटेदार चूहा हेजहॉग भी यहां पर लगातार देखा गया है। तिलपथ घाटी की हरियाली को और बढ़ाने के लिए अब यहां पर जगह-जगह पर चेक डैम बनाने की शुरुआत की गई है।

घाटी का इलाका होने के चलते यहां पर इस तरह की जगहें काफी हैं जहां

पर जल संरक्षण किया जा सकता है। पहली बार छह से ज्यादा जगहों पर पानी रोकने की व्यवस्था की गई है।

इस मानसून सीजन में इन सभी जगहों पर पानी रुक जाएगा, जिससे छोटे-छोटे जलाशयों का निर्माण होगा। इन जलाशयों से जहां जंगल की हरियाली बढ़ेगी, जीव-जंतुओं के लिए बेहतर पर्यावास उपलब्ध होगा वहीं भूमिगत जल का संभरण होगा और



2021

तिलपथ घाटी जैव विविधता पार्क में हरियाली बढ़ गई है। यहां चेक डैम बनाकर पानी रोकने की व्यवस्था से भूजल स्तर भी बढ़ेगा। • हिन्दुस्तान

भूमिगत जल के स्तर में बढ़ोतरी होगी।
स्थानीय पौधों से होगा संरक्षण : जैव विविधता पार्क कार्यक्रम के वैज्ञानिक प्रमुख डॉ. फेयाज ए खुदसर ने बताया कि जंगल में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय पौधों और झाड़ियों को लगाया जा रहा है। इसके साथ ही घसियाले हिस्से भी बनाए जा रहे हैं। इसके चलते पूरे जंगल में वन्यजीवों को नए और बेहतर पर्यावास मिलेगा।

अहम बातें

- 175 एकड़ जमीन पर स्थित है दिल्ली विकास प्राधिकरण का यह जैव विविधता पार्क
- 484 किस्म के पेड़ पौधे और वनस्पतियां इस जंगल में हैं मौजूद
- 125 प्रजाति के पक्षी और 55 प्रजातियों की तितलियों का यहां पर वास है

ई-वाहनों से जंगल की सैर कर सकेंगे

नई दिल्ली (प्र.सं.)। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में बैटरी संचालित वाहनों से जंगल की सैर होगी। इसके लिए 45 किलोमीटर लंबी एक पेरीफेरल सड़क का निर्माण होगा।

दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दिल्ली के इस एकमात्र अभ्यारण्य में हाल के दिनों में दुर्लभ घाटीदार लकड़बग्घों और तेंदुए की मौजूदगी लगातार दर्ज की जा रही है। अभ्यारण्य में मौजूद नीली झील को दिल्ली के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 45 किलोमीटर लंबी पेरीफेरल सड़क बनाने की योजना है। इस पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाया जाएगा, जिस पर बैठकर पर्यटक नीली झील तक जा सकेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **THE SUNDAY EXPRESS**, JUNE 5, 2022 :D-----

AAP's Atishi accuses L-G of interference again: 'Conspiracy to derail democracy'

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 4

HITTING OUT at new L-G Vinai Kumar Saxena for not informing the Chief Minister of a Delhi Jal Board (DJB) meeting for the second time, the AAP-led Delhi government called it a "conspiracy to derail democracy".

AAP MLA Atishi said, "The L-G is continuously making a mockery out of Delhi's constitutional arrangement... (and) is acting like a dummy of the BJP's central government... The Lieutenant Governor (has) the powers to formulate policy on only three matters — land, law and order, and police. For matters such as electricity, water supply, schools, hospitals, and to work for their betterment, the people of Delhi have elected the Aam Aadmi Party and CM Arvind Kejriwal."

The L-G on Saturday summoned officials from the DJB and also inspected two sites — Pappankalan sewage treatment plant and Dhansa regulator.

"On May 30, new L-G Saxena called a meeting of Jal Board officers. Two days after that, AAP raised questions on the legitimacy of the meeting. At that point, we thought the L-G was newly elected and perhaps was not aware about the constitutional provisions for the NCT of Delhi," said Atishi.

She added that other than the three domains that are under the L-G, the MCD could also be considered to be under him as it comes under the central government. She accused the L-G of neglecting matters under



Atishi said the L-G is making a mockery out of Delhi's constitutional arrangement

him such as cleanliness of the city which is the responsibility of the MCD, providing affordable housing by DDA, and maintaining the law and order situation.

"Delhi's law and order situation is in shambles since the new L-G took oath; there have been dozens of shameful incidents like sexual harassment on the Metro, and rape..." Atishi said.

She added that if the L-G goes beyond his assigned role from now on, "we will look upon it as a conspiracy to go against the elected government".

Reacting to the statements, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said "repeated diatribes of AAP leaders over inspection visits of the new L-G clearly shows the AAP government is fearing exposure of its failures".

Meanwhile, the L-G office in a statement said Saxena inspected Najafgarh drain during the day. "The L-G said a meeting will be convened in the next week with the Chief Minister and ministers and officers concerned to chalk out a concrete and time-bound plan of action... towards developing the Najafgarh drain..." it said.

Relocation chaos: Years on, market hubs lack basic infra

Risha Chitlangia

risha.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: The Chemical Market in the Integrated Freight Complex (IFC) at Narela wears a deserted look with the shutters and doors of most offices and godowns locked, and construction work on some plots abandoned midway.

Three years after the market was relocated from Chandni Chowk, following Delhi high court's 2019 orders following a court case regarding the decongestion of the Walled City, traders are yet to start operating from here.

While the Delhi Development Authority (DDA) provided them with land, traders say the lack of infrastructure and basic amenities such as water supply, sewerage, police station, banks, etc., at the new market has forced them to look for options outside Delhi. A majority of them have either purchased or rented godown space in Kundli (Haryana), just 5km away from Narela, or Sahibabad (Uttar Pradesh).

Raj Kumar Kapoor, president of Rang and Rasayan Vyapar Sangh, an association of dyes and chemical merchants, says that 720 traders were allotted plots at IFC in phases since 2001 on a 30-year lease. "Two decades have passed but there is no infrastructure in place," he says.

Like chemical traders, Chawri Bazaar's paper merchants were relocated to the IFC at Ghazipur in 2004-05 and the traders at the old tyre market on Gausala Road near Rani Jhansi flyover were relocated to Sanjay Gandhi Transport Nagar in 2015. These markets were relocated for either road-widening projects or to decongest the city.

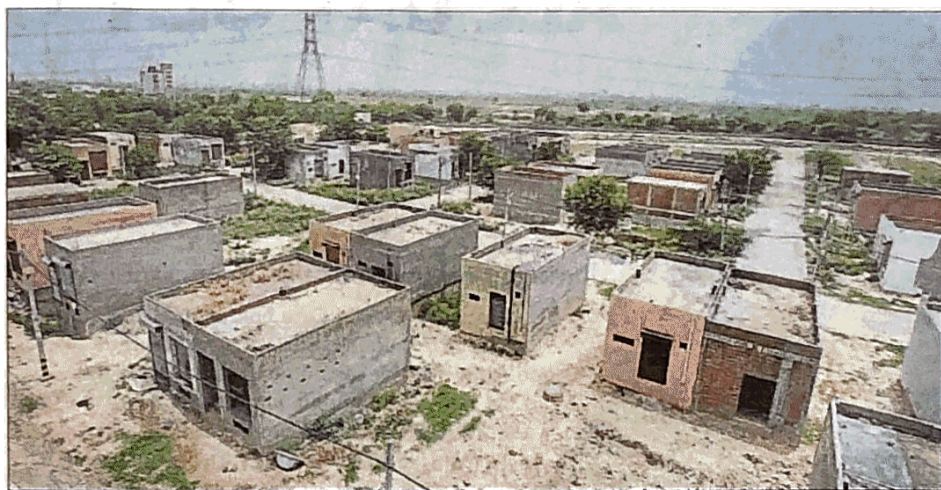
Their concerns are the same—lack of infrastructure notwithstanding, there are problems related to the plot sizes, a lack of flexibility to ply allied trade, etc., say traders in these markets.

HT takes a look at the issues.

Lack of infrastructure

While DDA had allotted plots to traders in 2001, traders actually started constructing their offices and workshops at Narela IFC 2019 onwards, following high court orders. While chemical traders were barred from operating even offices in Chandni Chowk, those involved in the business of dyes and colour were permitted by the erstwhile North Delhi Municipal Corporation (NDMC) to continue to run their offices in the Walled City.

Chemical traders say that there is no water supply in the



An aerial view of the almost abandoned Chemical Market in the Integrated Freight Complex (IFC) at Narela; (below) traders have to stock tyres on lanes due to paucity of space within shops in Sanjay Gandhi Transport Nagar.

RAJ K RAJ/HT PHOTOS

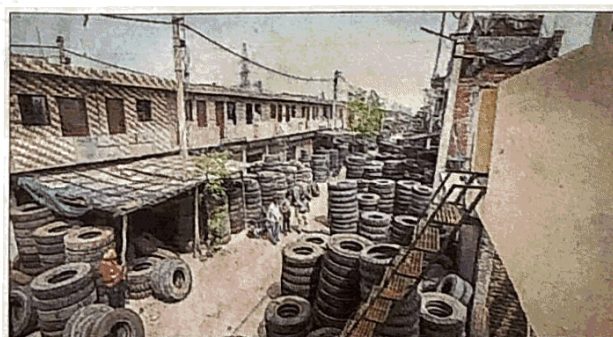
area and the sewers are in a bad condition. While a majority of traders have constructed offices and godowns at the new market, they don't have No Objection Certificates (NOC) from the fire department. "To get an NOC from the fire department, there has to be adequate arrangement for water. But there is no water supply in the area even after three years," says Sushil Goel, former president of Chemical Merchants' Association.

When contacted, a senior DDA official said, "The restoration work of water supply and sewerage in IFC Narela is in progress and likely to be completed by June 30, 2022. Water supply and sewerage services can be provided then."

Around 46km away from Narela is Ghazipur IFC—where paper merchants were relocated from Chawri Bazaar. They too complain about similar issues. Piyush Jain, president of Delhi Paper Merchants' Association, says, "The area is in a very bad condition. The roads are broken and the drainage system is not effective. During monsoon, the area gets waterlogged."

Not to mention the market is located near the Ghazipur landfill site. "Due to the stench, people can't sit in the market for long," Jain says.

At Sanjay Gandhi Transport Nagar, where old tyre market traders were relocated in 2015 to make way for a road-widening project near Rani Jhansi Road, traders say that the erstwhile NDMC, which was responsible for the upkeep of the area, had done no work. Even the roads in the market are broken. Traders say there is no drinking water supply in the area. "We have been just thrown on the outskirts of the city with no basic



infrastructure," says Hardev Singh Sethi, president of Guru Nanak Tyre Market Association.

Small plots, strict norms

Traders' associations of all the three areas complain about the small plots allotted to them, saying their trades require bigger plots. At the tyre market, traders have been provided 20-30sqm plots. As there is not much space, traders have stocked tyres on lanes. "We deal mostly in the sale and purchase of old truck tyres, which are very big. The space is not sufficient," Sethi says.

The Municipal Corporation of Delhi didn't comment on the matter.

Due to the lack of development in the area and the small size of the godowns, a large number of chemical traders have rented or bought godowns in neighbouring states. "There is no space to store huge chemical containers. This is one of the reasons why traders have set up godowns in Kundli (Haryana), Sahibabad (UP) etc. The state policies there are favourable for trade, and infrastructure is also in place," says Goel.

The strict land allotment norms at the IFC have also forced paper merchants to shift to neighbouring states. As per

DDA's norms, paper merchants can only store paper in the area, and not related items such as paper plates, cups, folders, etc. Traders say that the demand for paper has dropped over the years with even government offices gradually going paperless, and after the pandemic, the situation has worsened.

Their demands

Paper merchants have requested the DDA to allow allied businesses to operate from the area. The association held a meeting with DDA vice-chairman Manish Gupta in March this year.

According to a senior DDA official, "The matter is under consideration as they have a genuine concern. But no decision has been taken so far."

As for chemical traders, they want the DDA to complete the development work at the earliest. "We have also asked the DDA to provide us with additional land for storage," Goel says.

Tyre market associations want the market to be relocated, as their business has been impacted adversely. Sethi says, "We want the corporation to relocate us to Punjabi Bagh. It is impossible for us to continue our businesses here."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER **Hindustan Times** DATED **NEW DELHI MONDAY JUNE 06, 2022**

Govt launches green action plan for Delhi

HT Correspondent

htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: World Environment Day was celebrated across the capital on Sunday, with the Delhi government launching its 'Green Action Plan for Delhi', which includes a massive plantation drive across the city as well as introduce innovative concepts such as urban and rooftop farming.

The campaign was launched by Delhi's environment minister Gopal Rai, who celebrated the event with around 2,500 school children at the Indira Gandhi Indoor Stadium, also felicitating Delhi's 20 best eco-clubs.

The action plan consists of planting over 3.5 million saplings across Delhi this year, with the plantation drive to officially begin next month. Out of these, around 700,000 saplings will be distributed free of cost.

Rai said agencies will also be required to carry out a third-party audit to check the survival rate of these saplings, stating under the Green Action Plan, a roadmap will be prepared for the quality of plantation, soil moisture conservation and outreach and education among people in regards to protection of environment.

"Earth is our mother, and the Delhi Government, led by the chief minister, is doing everything possible to save and improve our mother nature. Working better in this direction, the Delhi government first converted buses to CNG, and now electric buses are also on the roads of the city," Rai said.

"Furthermore, as a result of the ongoing tree plantation campaign in Delhi, the green area in the city has gone up from being 20% in 2013, to 23.06% in 2021. In addition, Delhi has surpassed all other cities in the country in terms of per capita forest cover," the minister said, adding that the



The green action plan, which consists of planting 3.5 million saplings, was launched by environment minister Gopal Rai. ANI

As a result of the ongoing tree plantation campaign in Delhi, the green area in the city has gone up from being 20% in 2013, to 23.06% in 2021.

GOPAL RAI,
environment minister, Delhi

government was also pursuing urban farming to add to Delhi's green cover, while around 10,000 'world-class' parks were already being developed under the 'Green Park Green Delhi' campaign.

LG visits Yamuna biodiversity park

Meanwhile, Delhi lieutenant governor (LG) VK Saxena celebrated the World Environment Day at Delhi Development Authority's Yamuna Biodiversity Park in north Delhi, fol-

lowed by visits of a sewage treatment plant (STP) in Nehru Park in Chanakyapuri and a rainwater harvesting (RWH) site in the New Delhi Municipal Council (NDMC) area.

At the biodiversity hub, the lieutenant governor visited different ecological systems, including medicinal gardens, herbal parks, butterfly parks and its wetlands.

Saxena suggested park authorities to undertake plantation of sandalwood and moringa trees, apart from Bamboo.

"Climate change, water shortage, pollution, unseemly mounds of garbage and the plummeting ground water levels -- all of these are there for us to experience first-hand as residents of Delhi. We have to take urgent steps to reclaim and rebuild what we have already lost in our mindless pursuit of lopsided consumption and development," Saxena said.

Delhi's chief secretary and the Delhi Development Authority vice-chairperson also accompanied the lieutenant governor during the visit to the biodiversity park.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--

हिन्दुस्तान

DATED-- नई दिल्ली, सोमवार, 6 जून 2022

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की घोषणा, ग्रीन दिल्ली थीम पर विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी

सरकार 10 हजार पार्क विकसित करेगी

हरित उत्सव

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में दस हजार पार्कों को विकसित किया जाएगा। ग्रीन पार्क-ग्रीन दिल्ली की थीम पर इन पार्कों में विश्व स्तरीय सुविधाएं जुड़ाई जाएंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 'हरित उत्सव' कार्यक्रम में कही।

सरकार लगातार कर रही काम : पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के चलते पहले बसों को सीएनजी में बदला गया। अब इलेक्ट्रिक बसें भी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में चलाए गए सघन पौधरोपण के चलते दिल्ली के हरित क्षेत्र में इजाफा हुआ है।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार अर्बन फार्मिंग को लेकर काम कर रही है, जिससे न केवल हरित क्षेत्र बढ़ेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। साथ ही, दिल्ली की दस हजार पार्कों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए ग्रीन पार्क-ग्रीन दिल्ली थीम पर अभियान की शुरुआत की गई है। पर्यावरण मंत्री ने



हरित उत्सव के दौरान रविवार को शपथ लेते शिक्षक और छात्र। • एजेंसी

बच्चों को दिलाई शपथ

- हरित उत्सव कार्यक्रम में अलग-अलग विद्यालयों के लगभग ढाई हजार बच्चे शामिल रहे।
- इस मौके पर दिल्ली के 20 सबसे अच्छे ईको क्लबों को पुरस्कृत किया गया।
- कार्यक्रम के दौरान बच्चों और शिक्षकों को पर्यावरण बचाने के लिए शपथ भी दिलाई गई।

दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान दिल्ली के लोगों से भी किया। उन्होंने कहा कि

दिल्ली को मिला 'दिल'

करोल बाग इलाके में एक सड़क पर सजावटी प्रदर्शन में लगे प्रतीक चिह्न 'दिल' के कथित तौर पर चोरी हो जाने के करीब एक महीने बाद रविवार को दिल्ली को अपना 'दिल' वापस मिल गया। निगम अधिकारियों ने कहा कि दिल के आकार का नया एलईडी सकेतक उस हिस्से में फिर से लगाया गया है, जहां से यह गायब हो गया था। घटना मई शुरुआत में रिपोर्ट हुई थी।

जनसहभागिता से ही पर्यावरण को बेहतर और प्रदूषण मुक्त बनाने का रोडमैप बनेगा।

जैव विविधता पार्क में लगाएं चंदन और सहजन के पेड़

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर्यावरण दिवस के मौके पर रविवार के दिन यमुना जैव विविधता पार्क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पार्क में चंदन और सहजन के पेड़ लगाने की सलाह दी। कहा कि इससे न सिर्फ पार्क की ऑक्सीजन देने की क्षमता में इजाफा होगा बल्कि आर्थिक तौर पर भी इसका फायदा मिलेगा।

इस मौके पर उप राज्यपाल ने दिल्ली के विश्वविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित किया। कविता की दो पंक्तियों को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि रोज गिराते हैं पत्ते मेरे। फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ इसानों द्वारा की जाने वाली हर तरह की गतिविधि को सहन कर लेते हैं और इसके बावजूद उन्हें फल, खाना, छाया, लकड़ी और जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे पेड़ के जीवन से सीखें और उसका सम्मान करें। उप राज्यपाल ने पार्क के



चंपा का पौधा लगाया

उप राज्यपाल ने दिन में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के नेहरू पार्क में बनाए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने नेहरू पार्क में चंपा का पौधा भी लगाया। परिषद उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, एनडीएमसी सदस्य कुलजीत सिंह चहल, विशाखा सेलानी व अन्य मौजूद रहे।

जलाशयों, जड़ी-बूटी पौधों के उद्यान और तितली पार्क का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, प्रो. सीआर बाबू, डॉ. फैयाज ए खुदसर व अन्य लोग मौजूद रहे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | सोमवार, 6 जून 2022

बायोडायवर्सिटी पार्कों को अब और अधिक बेहतर बनाना होगा : एलजी

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एलजी ने यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क का किया दौरा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क अर्बन फॉरेस्ट का उदाहरण हैं। अब समय आ गया है कि इन्हें अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एलजी वी. के. सक्सेना रविवार को यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क पहुंचे। उनके साथ डीयू के स्टूडेंट्स के साथ डीडीए के अधिकारी, प्रोफेसर सीआर बाबू समेत कई अधिकारी थे।

पार्क के साइटेस्ट ईचार्ज डॉ. फैयाज ए खुदसर ने एलजी को पार्क की विशेषताओं के बारे में बताया। एलजी ने एनडीएमसी एरिया में नेहरू पार्क के एसटीपी और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग साइट का निरीक्षण



एलजी ने नेहरू पार्क एसटीपी का भी दौरा किया

भी किया। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में उन्होंने मेडिसन गार्डन, हर्बल पार्क, बटरफ्लाई पार्क और झीलों का दौरा किया। एलजी ने कहा कि यह अर्बन फॉरेस्ट

सुझाव

- एलजी ने इन पार्कों में बांस के साथ साथ चंदन और मोरिंगा के पेड़ लगाने पर जोर दिया
- नेहरू पार्क के एसटीपी और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग साइट का भी निरीक्षण किया

का एक बेहतर उदाहरण है। अब समय आ गया है कि इन पार्कों को अगले स्तर पर ले जाया जाए और इन्हें और अधिक बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अब यहां बांस के साथ चंदन और मोरिंगा के पेड़ लगाए जाने चाहिए। इससे यहां ऑक्सीजन की क्षमता भी बढ़ेगी और पार्क आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगा। वहीं, उन्होंने इस बात

पर भी जोर दिया कि बायोडायवर्सिटी पार्क में बचाया गया और रिचार्ज किया गया पानी शहर की सप्लाय में कैसे काम में लाया जा सकता है, इसे लेकर प्लानिंग होनी चाहिए। एलजी ने छात्र छात्राओं से बात करते हुए कहा कि पेड़ मानव जाति का हर प्रहार सहने हुए भी उन्हें फल, फूल, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि प्रदान करते हैं। इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी होगी। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी को बचाकर, बरसाती नालों को बेहर बनाकर हम भूजल स्तर बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से राजधानी को पानी की किल्लत से छुटकारा मिल सकता है। यमुना को हमें नाले की जगह नदी समझना होगा और नदी में सीवर न जाए यह हम सब का फर्ज है।

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | सोमवार, 6 जून 2022

आईजीआई एयरपोर्ट पर अब बारिश में नहीं भरेगा पानी

लंबे समय बाद मिली डीडीए के ड्रेन प्रोजेक्ट को मंजूरी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

मॉनसून के दौरान आईजीआई एयरपोर्ट पर भरने वाले बरसाती पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बनाए गए ड्रेन के प्रोजेक्ट को अब वन विभाग की मंजूरी मिल गई है। इस ड्रेन के जरिए एयरपोर्ट से यह पानी सीधे द्वारका लाया जाएगा। यहां यह भारत वंदना पार्क की झीलों में एकत्रित किया जाएगा। वन विभाग की मंजूरी के अभाव में पिछले करीब दो सालों से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ था।

वन विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए 693 प्रोजेक्ट को हटाने की मंजूरी दी है। इनमें से 637 पेड़ों को ट्रांसप्लान्ट किया जाएगा और 56 पेड़ काटे जाएंगे। यह ड्रेन अगले साल के अंत तक बनकर तैयार होने की संभावना है। डीडीए अधिकारियों के अनुसार, ड्रेन की लंबाई करीब 3 किलोमीटर होगी और यह एयरपोर्ट से भारत वंदना पार्क कर बनेगी। इसके बाद यह ट्रंक ड्रेन-2 से जुड़ जाएगा। इस ड्रेन का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी होगा और यह द्वारका सेक्टर-8 बागडोला गांव के पास से गुजरेगा। डीडीए को इस प्रोजेक्ट



- एयरपोर्ट का बरसाती पानी इस ड्रेन के जरिए द्वारका जाएगा
- यह पानी भारत वंदना पार्क की झीलों में एकत्रित होगा

के लिए वन विभाग में 3.95 करोड़ रुपये जमा करवाने होंगे। यह पेड़ों को काटने के एवज में होंगे। वहीं, डीडीए को 6930 पौधों की कीमत भी देनी होगी।

डीडीए अधिकारियों के अनुसार, ड्रेन के लिए वर्क अवार्ड मार्च 2020 में कोविड महामारी से पहले ही किया जा

इस साल मॉनसून में नहीं होगी समस्या

डीडीए अधिकारियों के अनुसार, इस साल द्वारका सेक्टर-8 में जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी नालों की सफाई की जा चुकी है। सेक्टर-8 और सेक्टर-23 में झीलों भी बनाई हैं। बारिश का पानी इन झीलों में भर जाएगा। यह ड्रेन 20 मीटर गहरी और दो मीटर चौड़ी होगी। ड्रेन रेवाड़ी रेलवे लाइन से शुरू होकर आगे ट्रंक ड्रेन 2 में गिर जाएगा। इस ड्रेन के जरिए करीब एक करोड़ लीटर पानी सेक्टर-20 में बन रहे भारत वंदना पार्क की झीलों में डाला जाएगा। अतिरिक्त पानी ड्रेन नंबर-2 में चला जाएगा।

चुका था। लेकिन इसके बाद वन विभाग की मंजूरी मिलने में करीब दो सालों का समय लग गया। अब हमें ट्रांसप्लान्टेशन के लिए करीब 4 करोड़ रुपये जमा करने हैं। काम शुरू करने से पहले ट्रि प्लान्टेशन के काम को पूरा करने में कुछ महीनों का समय लगेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JUNE 6, 2022

DATED

On environment day, LG at park with DU students



Saxena suggested that the park undertakes plantation of trees like sandalwood and moringa to increase its 'oxygenating capacity'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Sunday visited the Yamuna Biodiversity Park developed by DDA to celebrate World Environment Day with students of Delhi University. Saxena suggested that the park undertakes plantation of sandalwood trees, moringa trees, bamboo, etc to increase the 'oxygenating capacity' of the park, and also add to its financial viability.

Appreciating scientists, officers, and their teams for creating an exemplary model of urban forestry in the midst of concrete jungles, LG emphasised that time has come to take the park to the next level by innovating, upscaling and reinventing. He also stressed on the need to explore the possibility of using the water conserved and recharged by parks for augmenting the supply to the city with an aim of making Delhi self-sufficient.

He described groundwater recharge through conservation of rain, flood, and storm drain water with an aim to make Delhi self-sufficient for its water requirements, as priority. He stressed on the rejuvenation of Yamuna by ensuring zero untreated sewerage discharge into the river in a time-bound manner.

He said work had started on clearing garbage mountains that bring international shame to the capital, expressing hope that with combined efforts, they will soon see not on-

ly razing of these legacy mounds but also a functional system in place for recycling and processing concurrent garbage in the city.

Saxena underlined that environmental degradation and resultant catastrophic effects are no more topics of academic discourse and seminar discussions, they are also for people to see. Climate change, water shortage, choking pollution, unseemly mounds of garbage, and plummeting groundwater levels are evident for Delhiites,

LG SAYS

Environmental degradation and resultant catastrophic effects are no more just topics of academic discourse

he said, while interacting with students from Shiva Ji College of Delhi University.

He said the biggest challenge on the environmental front today is the sustainable and long-term management and disposal of solid waste and sewerage. "To plan for the future and simultaneously rejuvenate what we have lost already was imperative and for this, all of us will have to come together and work in a committed and concerted manner," the LG said. He also visited an STP in Nehru Park in Chanakyapuri and a Rain Water Harvesting site in the NDMC area.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

DELHI THE HINDU
SATURDAY, JUNE 4, 2022

NAME OF NEWSPAPERS

DATED

DDA plans to sell flats on first come, first served basis in July

Move aimed at reviving interest of homebuyers, says official

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) is planning to sell its unsold housing inventory from previous schemes on a first come, first served basis in July, said a senior DDA official on Friday.

Only 5,227 of 18,335 flats in the DDA's special housing scheme 2021 – in areas such as Dwarka, Rohini, Narela and Jasola – found takers after the draw of lots in April. In March, the urban body had announced that it had approved an amendment to its housing regulations, which prohibited people who already owned a flat or a plot in Delhi from buying its flats.

The official said the relaxation in the amendment is likely to receive a nod from



Many allottees surrendered flats in Narela because of connectivity issue, said the official. ■ FILE PHOTO

the Union Ministry in the coming month, while adding that the urban body will not start any new housing projects in the near future.

“The flats are being surrendered on a recurring basis, so it is better to sell them on a first come, first served

basis. The reason for surrendering of flats in Narela is the connectivity issue while those surrendering their flats in Jasola complain of high prices,” said the official, adding that the urban body is looking to curb the allotment of flats to non-serious buyers.

The DDA's decision to dispose of its unsold inventory is being seen as a move to revive the interest among homebuyers, said the official.

Previously, *The Hindu* had reported that all DDA housing schemes since 2014 have had a poor response with a majority of the flats, including those listed in the 2017, 2019 and early 2021 schemes, remaining unsold – an observation that the DDA had admitted to in a document.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS 6 जून • 2022

सहारा

ED

गंदगी के अंबारों में रहने को मजबूर हैं निवासी

मेरी दिल्ली मेरी शान शीर्षक अब इतिहास की बात हो गई है। कापसहेड़ा करीब पिछले 8 सालों से चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा फैला रहता है। ऐसा कपास हेड़ा गांव में जगह-जगह देखने को मिलता है। सड़कों की सफाई और कूड़ा उठाने का काम निगम कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन खाली प्लांट कूड़ेदान बन चुके हैं। उन प्लांट्स में से कूड़ा उठाना किसी का काम नहीं। वहां मच्छर पैदा नहीं होता क्या। पार्श्व को इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन निगम अधिकारियों का कहना है कि किसी के प्लांट से कूड़ा उठाने का काम उनका नहीं। 2014 से आज तक कोई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल एक बार पार्श्व ने जेसीबी से प्लांट का कूड़ा निकलवाया। वहां फिर से 6 से 8 फुट ऊंचा कूड़ा का ढेर आज भी लगा है। समझ में नहीं आता कि दिल्ली की सुंदरता के बारे में सुंदरता का ख्याल रखने के लिए कोई विभाग काम कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो उसे खाली प्लांट में गंदगी नहीं दिखाई देती क्या। मेरा दिल्ली सरकार और एमसीडी के आला अधिकारियों से अनुरोध है कि हमारे कापसहेड़ा गांव को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें।

उमेश कुमार सरिन, साईकुंज, कापसहेड़ा।
डीटीसी की ए सी बसों में साफ सफाई की कमी

डीटीसी ने दिल्ली में लाल रंग की एसी बस तो खूब चलाई। यह कोई नहीं देखता कि बस में साफ सफाई हो रही है कि नहीं। मेरा डीटीसी के उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि इस वजह से नागरिकों की असुविधा को

ध्यान में रखते हुए सभी बसों को डीटीसी डिपो से तभी रूट पर भेजा जाए अगर उसमें सफाई ठीक से कराई गई है।
राजेंद्र सिंह, गांव पंडवाला कलां, नजफगढ़।

पार्क में आसामाजिक तत्वों का जमावड़ा
बुज विहार अपार्टमेंट, पीतमपुरा में पुष्पांजलि एनक्लेव के पास है। इस सोसाइटी के साथ एक डीडीए का पार्क है। डीडीए ने पार्क अच्छा बनाया है। इस बुज विहार पार्क में शाम को आसामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ओवारा लड़के और लड़कियां यहाँ घूमते, शोर एवं अश्लील हरकतें करते हैं जिससे बुज विहार निवासियों को परेशानी होती है। हमारा दिल्ली पुलिस के संबंधित उच्चाधिकारी से अनुरोध है कि इस पार्क में पुलिस गश्त इंतजाम कर निवासियों को राहत प्रदान करें।
बृज विहार के

दुखी निवासी।

दिल्ली की जनता पीने के स्वच्छ पानी के लिए त्रस्त और जल विभाग मस्त
शकरपुर डी ब्लॉक की बंद गली में गिनती के सात मकान हैं। जहां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर का बदबूदार पानी पिछले कई महीनों से सप्लाई हो रहा है। आसपास की सड़क और गली के नीचे की पाइप लाइन पुरानी होने से आए दिन धंस जाती है। इनकी कई बार मरम्मत होने के कारण जगह-जगह लगे हुए जोड़ खुलने से पास की ध्वस्त

हो चुकी सीवर लाइन का बदबूदार गंदगी पीने के पानी में मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रही है। सड़क टूट कर नीचे धंसने से गड़बड़े हो जाते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर इन लाइनों को बदल देना चाहिए, जिससे क्षेत्र की जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके और सड़कों पर गड़बड़े भी न हो। दिल्ली सरकार के संबंधित उच्चाधिकारियों से अनुरोध है, इस मामले में कार्रवाई कर राहत दिलाएं।

पीयूष, डी 64 शंकरपुर, लक्ष्मी नगर।

सरकार द्वारा पुराने वाहनों को नष्ट करने का कानून रुपए की बर्बादी

सभी दोपहिया एवं चार पहिया निजी और कमर्शियल वाहनों को एनजीटी के द्वारा 10 और 15 साल

होने पर नष्ट करने के जो नियम बनाए गए वह नियम केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए तो ठीक है। निजी वाहनों के हक में ठीक नहीं। सभी धुली-भांति जानते हैं कि ज्यादातर निजी वाहन 15 वर्षों तक कुछ ही किलोमीटर तक चल पाते हैं, परिवार की सुविधा के लिए आवश्यकता होने पर ही वाहन को सड़क पर निकाला जाता है और निजी वाहनों के रख-रखाव का भी ध्यान रखा जाता है। अतः निजी वाहनों को रद्द घोषित करके नष्ट करना लोगों पर अन्याय करना है। लोग बड़ी मुश्किल से एक-एक पैसा जोड़कर लाखों

रुपए खर्च कर इस सुविधा को प्राप्त करता है लेकिन सरकार में बैठे मुट्ठी भर लोग कुछ घंटों की मीटिंग से ही हर किसी को इस सुविधा को वंचित कर लाखों रूपया कबाड़ में फेंकने पर मजबूर कर देते हैं। सरकार को इस पर उचित विचार कर निजी वाहनों के नष्ट करने के नियम को वापस लेकर जनता को राहत देनी चाहिए।

प्रवीण कालड़ा, लक्ष्मी नगर विकास मार्ग।

कब दुरुस्त होगा कोटला अलीगंज मार्ग
प्रशासनिक उपेक्षाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही के चलते पिछले कई वर्षों से दक्षिणी दिल्ली का कोटला अलीगंज मार्ग बंदहाल पड़ा है। बड़े-बड़े गड़बड़े होने से न सिर्फ आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहता है वरन् दुर्घटनाओं की संभावनाएं हर समय बनी रहती हैं। सबसे बदतर हालात तो बरसात होने से हो जाते हैं जब संपूर्ण शस्ता कीचड़नुमा बन जाता है। ऐसे हालात में बुजुर्गों और महिलाओं के चोटिल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। विदित हो कि क्षेत्र की यहां सबसे बड़ी सब्जी मंडी और किराना मार्केट होने से हर समय भीड़ रहती है और यातायात भी बहुत रहता है। बावजूद इसके न तो प्रशासन और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कानों पर जुं रेंग रही है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और लोगों में भयंकर रोष वयाप्त है। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, एसडीएमसी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि तत्काल सड़क का पुनः निर्माण कराया जाए।

सोमदत्त तेंवर, गांव मोची बाग, नानक पुरा।



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala

NAME OF NEWSPAPERS

सोमवार, 6 जून 2022

DATED

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, सोमवार, 06 जून 2022

जैव विविधता पार्क में एलजी ने छात्रों संग मनाया पर्यावरण दिवस

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को डीडीए की ओर से विकसित यमुना जैव विविधता पार्क का दौरा कर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया।

उनके साथ मुख्य सचिव नरेश कुमार, डीडीए के उपाध्यक्ष मनोष गुप्ता और डीडीए के जैव विविधता पार्क के प्रभारी प्रो. सीआर बाबू, प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डॉ. फैयाज ए खुदसर मौजूद थे। उन्होंने चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में एक एमटीपी और एनडीएमसी क्षेत्र में एक वर्षा जल संचयन स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों, विभागों और अधिकारियों

कचरा प्रबंधन के लिए सभी एजेंसियों को काम करने की सलाह दी

को एक प्रभावी, समयबद्ध और समन्वित तरीके से कचरों से निपटने के लिए काम करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने पार्क में विकसित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का मुआयना किया। उन्होंने यमुना नदी की विरासत को पुनर्जीवित करने और कंक्रीट के जंगलों के बीच सहरी वानिकी का एक अनुकरणीय मॉडल बनाने के लिए वैज्ञानिकों, अधिकारियों और उनकी टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की। बृहत्

यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क का दौरा स्वच्छ हवा के लिए पार्क में चंदन और मोरिंगा के लगाए वृक्ष: एलजी



नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को डीडीए द्वारा विकसित यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क का दौरा किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, डीडीए के वीसी प्रो. सीआर बाबू, प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डॉ. फैयाज ए खुदसर, पार्क के प्रभारी वैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने एनडीएमसी के चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में एक एमटीपी और एनडीएमसी क्षेत्र में एक वर्षा जल संचयन स्थल का भी दौरा किया। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में उपराज्यपाल ने विकसित किए गए फाउंड्री पर यात्रा करते हुए मौजूदा वनस्पतियों और जीवों में गहरी रुचि ली। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पार्क में बांस के अलावा चंदन की लकड़ी और मोरिंगा के पेड़ लगाए जाते हैं। इससे न केवल पार्क की ऑक्सीजन क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि इसकी वित्तीय व्यवहार्यता भी बढ़ेगी, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ हो जाएगा।

पंजाब केसरी 6 जून, 2022

उपराज्यपाल ने किया यमुना जैव विविधता पार्क व नेहरू पार्क का दौरा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को डीडीए द्वारा विकसित यमुना जैव विविधता पार्क का दौरा कर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इसके बाद उन्होंने चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में एक एमटीपी और एनडीएमसी क्षेत्र में वर्षा



→ पार्क का दौरा करते उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना।

जल संचयन स्थल का दौरा किया। यमुना जैव विविधता पार्क में उनके साथ मुख्यसचिव, डीडीए वीसी, डीडीए, प्रसिद्ध पर्यावरणविद् प्रो. सीआर बाबू व पार्क के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. फैयाज ए खुदसर भी मौजूद रहे।

एलजी ने औषधीय उद्यान, हर्बल पार्क, तितली पार्क और पार्क में विकसित आर्द्र भूमि और जल निकायों का दौरा किया। एलजी ने दिल्ली की आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शहर को पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पार्कों द्वारा संग्रहित और रिचार्ज किए गए पानी के उपयोग की संभावना तलाशने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस दौरान एलजी ने मौजूद छात्रों को पेड़ों का महत्व बताते हुए कहा कि पेड़ मनुष्य और प्रकृति की सभी प्रकार की हिंसा को झेलते हैं और फिर भी हमें फल,

भोजन, छाया, लकड़ी और जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं। उन्होंने युवाओं को पेड़ से सीखने और उसका सम्मान करने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और जीवन विज्ञान के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए एलजी ने गुजरात में नर्मदा नहर के परिदृश्य और राजस्थान में उदयपुर के पास शुष्क क्षेत्र में असम के बांस की विशेष किस्मों के रोपण को याद किया। एलजी ने इस बात को रेखांकित किया कि पर्यावरणीय क्षरण और इसके परिणामी विनाशकारी प्रभाव अब एकैडमिक डिबेट और सेमिनार चर्चा के विषय नहीं हैं, वे हम सभी के देखने के लिए हैं।